कृषि अर्थव्यवस्था में नाबार्ड की योजनाओं और मूल्यांकन का विश्लेषण

डॉ. बसंती मैथ्यू
वाणिज्य विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत.

शोध सारांश
कृषि अर्थव्यवस्था – भारत का मूल आधार है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ कृषक बसते हैं, परन्तु आज के समय में ये कृषक बैंकों की नीतियों ऋण, बीमा, योजनाओं के गिरफ्त में आ गये हैं, जिसमें सूखा, बाढ़, मुख्य कारण है, इन कृषकों के जीवन को तथा कृषि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान करने में बैंकों का विशेष योगदान रहा है, जिसमें नाबार्ड प्रमुख है जो रिजर्व बैंक की नीतियों के आधार पर अन्य बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है और जिसके माध्यम से अन्य बैंक कृषकों को ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें किसान केडिट कार्ड योजना, फसल ऋण योजना तथा नेवकान्स जो कृषकों को परामर्श की सेवायें प्रदान करता है। जिसके आधार पर नाबार्ड का राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ मिलकर वित्त योजना तैयार की जाती हैं। कृषि परियोजनाओं को वित्त पोषण को बढावा मिलता है। इन योजनाओं के आधार पर परियोजना रिपोर्ट शामिल है।

I प्रस्तावना

देश में बैंकिंग जगत के इतिहास में सबसे बड़े प्रयासों में से एक प्रयास के रूप में नाबार्ड ने बैंकों की ओर बैंकिंग प्रक्रिया में तेजी पाई। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का कृषि ऋण वित्त एवं विकास के आधार पर कार्य करता है। नाबार्ड के विषय में कृषकों को जागृत करना है, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन का आधार केन्द्र हैं जो उच्चतम अर्थव्यवस्था का आधार केन्द्र है, जो उच्चतम अर्थव्यवस्था का माध्यम हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि वित्तीय योजनाओं का नाबार्ड की विशेष योजनाओं के संदर्भ में अभिलेख किया गया है। नाबार्ड की सहभागिता के आधार पर राष्ट्रीकृत बैंक की नीतियों का मूल्यांकन शामिल किया गया है।

वर्तमान कृषि व्यवस्था में कृषकों की विशेष भूमिका रही। जिसमें स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम, संयुक्त देयता समूह, कृषक क्लब, वाटर शेड विकास, संस्थागत विकास पर बड़ी ही योजनानुसार कार्य सम्पादित किया। कृषि अर्थव्यवस्था का सफल संचालन बैंकों के माध्यम से किस प्रकार किया जाये इस पर विशेष रूझान लाने का प्रयास है। जिसमें बैंकों की ऋण नीतियों अल्पकालीन ऋण पूंजी दीर्घकालीन ऋण को विनियोजित करना भी शामिल है।

देश में नाबार्ड ने सहकारी बैंकों की शाखाओं को बैंकिंग तथा वित्तीय समावेश रूप प्रदा किया –

II उद्देश्य, विधि तथा परिकल्पनाएं एवं सीमायें

(क) उद्देश्य

(i) बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण प्रदान की जानकारी का विश्लेषण करना ।
(ii) नाबार्ड के द्वारा विभिन्न बैंकों की पुर्नवित्त योजनओं का अध्ययन व मूल्यांकन ।
(iii) कृषि अर्थव्यवस्था के आधार पर कृषकों के अनुदान की जानकारी प्रदान करना।

(ख) अनुसंधान विधि, न्यादश आधार क्षेत्र

(i) कृषि अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिये कृषकों को प्रश्नावली के आधार पर प्रमाप विचलन कोई स्वायर टेस्ट किया।
(ii) प्रश्नावली के आधार पर कुल संख्या के आधार पर अभिमत प्राप्त किये गये हैं जो कि शोध के उददेश्य में पूर्णत: सहायक सिद्ध है।

इसमें भोपाल संभाग के समस्त जिले भोपाल रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा की नाबार्ड वित्तीय योजना को शामिल किया गया।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का योगदान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्टेट बैंक आदि भोपाल संभाग की प्रमुख शाखायें।

(ग) परिकल्पनायें

(i) कृषि अर्थव्यवस्था पर बैंकों की वित्तीय नीतियों तथा योजनाओं का क्रियात्मक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
(ii) नाबार्ड की वित्तीय योजना, कार्य विधि को क्रियान्वित करने से कृषक जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) अध्ययन की सीमायें

(i) न्यादर्श के रूप में भोपाल संभाग के जिलों को शामिल किया गया है।
(ii) न्यादर्श प्रत्येक जिले के राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड वित्तीय रिपोर्ट से लिया गया है।

III विश्लेषण

नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत विकास योजना के रूप में आधार वर्ष 2013–14 के दौरान रू. 17353 करोड़ का संवितरण किया। जो 6.51 प्रतिशत की वृद्धि है। कुल पुनर्वित्त परिचालन वर्ष 2013–14 में रू. 102089 करोड रहा। जिसमें 24 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि हुई। राज्य सरकारों के तहत आईडीएफ के तहत रू. 16292266 करोड की उपलब्धि दर्ज की गई। सहकारी बैंकों से सीधे ऋण के रूप में तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल किया। जिसका रू. 3385 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया।

IV निष्कर्ष

नाबार्ड ने कृषि विकास के लिए फसल एकीकृत ऋण मामलों की पहचान करने में बैंकों की मदद करनी चाहिए। शासकीय विभागों द्वारा बेहतर समन्वय स्थापित कर अनुदान वितरण शीघ्रता से किया जाये, वर्तमान में किसानों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले किसान केडिट कार्डो के लिये निष्पादित किये जाने वाले बंधक विलेखों पर प्रतिभूति ऋण की राशि 4 प्रतिशत की दर स्वम्प शुल्क देय है। बागवानी क्षेत्रों के विकास की वृहत योजना को कार्यरूप देने के लिये विशेष कार्यक्रम को क्रियान्वित किया। बारहवीं पंचवर्षीय सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उददेश्य से अतिलघु सिंचाई टेक्नॉलाजी भी व्यापक सार पर बढावा देने का प्रयास है। हथकरघा उत्पादन व विपणन के लिये भारत सरकार की बीमा योजना का आरंभ किया गया। नाबार्ड द्वारा तैयार योजनाओं के आधार पर ही बैंक शाखा, जिला स्तर पर ऋण योजनायें तैयार की जायेगी। विशेष बैठकों में संबंधित एजेन्सियों के साथ व्यापक विचार विमर्श का प्रावधान किया गया है।

नाबार्ड एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कृषि विपणन संबंधी आधारभूत सुविधा श्रेणीकरण, सुदृढ़ीकरण भी योजना का आरंभ किया गया, जिसमें सूक्ष्मवित्त विकास को बढ़ावा दिया गया।

संदर्भ ग्रंथ

[1] डॉ. विष्णु दत्त नागर (2009) "भारतीय अर्थव्यवस्था'मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल (म0प्र0)

[2] डॉ. वल्लभ दास मेहता (2009) " भारतीय अर्थव्यवस्था" मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल (म0प्र0)

[3] आर.एन. कोहेन "कृषि अर्थव्यवस्था" म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल मध्यप्रदेश

[4] कपूर सुदर्शन कुमार" भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर

[5] गुप्ता कन्हैयालाल "भारत की आर्थिक समस्या कृषि अर्थव्यवस्था " उ.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

[6] शर्मा आर.पी. "ग्रामीण अर्थव्यवस्था " कल्याणी प्रकाशन नई दिल्ली

[7] जैन हेमचन्द्र "कृषि वित्त व व्यवहार " म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

[8] वार्ष्णेय पी.एन. बैंकिंग विधि एवं व्यवहार" सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली

[9] www. nabard.org.in नाबार्ड परिदृश्य

[10] www. sbi.org.in वित्तीय रिपोर्ट

[11] www.slbc.org.in वित्तीय रिपोर्ट